

नव भारत

अंबेडकर जयंती

महिलाएं करेंगी लोकतंत्र मजबूत

संसद एक नया इतिहास रचने के करीब : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली, 13 अप्रैल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के दौरान महिलाओं की भूमिका, प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण को लेकर व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया. उन्होंने देशभर की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक नारी शक्ति को समर्पित फैसले की ओर बढ़ रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, जो सामाजिक न्याय और समानता को नई दिशा देगा. उन्होंने बताया कि 2023 में नए संसद भवन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पहला कदम उठाया गया था और अब इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है. 16 अप्रैल से संसद के विशेष सत्र में इस पर व्यापक चर्चा होगी.



महिलाओं से सक्रिय भागीदारी की अपील

प्रधानमंत्री ने महिलाओं से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं. अपने संसदों से संवाद करें और इस विषय को गांव-गांव तक पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसी एक दल का नहीं, बल्कि पूरे देश और सभी राजनीतिक दलों का सामूहिक प्रयास है. उन्होंने बताया कि भारत में पंचायत से लेकर उच्च पदों तक महिलाओं ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है. वर्तमान में लाखों महिलाएं स्थानीय निकायों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और कई राज्यों में उनकी भागीदारी 50 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी दलों के सहयोग से यह अधिनियम पारित हुआ था और अब इसे लागू करना प्राथमिकता है, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होगा.

प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड और यूपी का दौरा आज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे. इस दौरान वे कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन प्रमुख है. प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11.15 बजे सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे के ऊंचे खंड पर बने नवजीव गलियारे का दौरा और समीक्षा करेंगे. यह गलियारा मानव-व्ययजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से विशेष रूप से डिजाइन किया गया है. इसके बाद प्रधानमंत्री देहरादून पहुंचकर जय मां दात काली मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे. यह मंदिर क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है.

संसद में 16 से विशेष सत्र भी होगा

महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करने के उद्देश्य से 16 अप्रैल को संसद का एक सत्र बुलाया जा रहा है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने महिलाओं के लिए आरक्षण को नई जगह पर आगे बढ़ा दिया था.

2 बड़े संशोधन की प्लानिंग

सरकार ने दो बड़े संशोधनों की योजना बनाई है, जिसमें एक अलग परिसीमन विधेयक भी शामिल है. महिलाओं के लिए रिजर्वेशन तय करने के लिए इन दोनों विधेयकों को संवैधानिक संशोधन के तौर पर पारित किया जाना जरूरी है.

अम्बेडकर जयंती पर आज सार्वजनिक अवकाश

भोपाल, 13 अप्रैल. केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इसी क्रम में राज्य सरकार ने भी 14 अप्रैल को डॉ. अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर पूरे मध्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.

वनरक्षक की ट्रेक्टर से कुचलकर हत्या करने वाला ड्राइवर पकड़ा

नवभारत न्यूज

मुंरेना, 13 अप्रैल। दिमनी क्षेत्र के रानपुर में 8 अप्रैल को चंबल नदी की रेत से भरे ट्रेक्टर-ट्रॉली से कुचलकर वनरक्षक हरिकेश गुर्जर की हत्या करने वाले ड्राइवर विनोद कोरी पुत्र रामकुमार कोरी निवासी ग्राम कुथियाना को दिमनी पुलिस ने 13 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर विनोद कोरी के



हरिकेश गुर्जर हत्याकांड में अब तक 3 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। घटना में प्रयुक्त किए गए ट्रेक्टर के मालिक सोनू चौहान और पवन तोमर को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी थी। फरार चल रहे ड्राइवर विनोद कोरी पर 10 हजार का इनाम घोषित किया गया था। उसकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दक्षिण दे रही थीं। सोमवार को विनोद कोरी को दिमनी पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस द्वारा आरोपी विनोद से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

वोटर लिस्ट से नाम कटे तो वोट देने का अधिकार नहीं : सुको

नई दिल्ली, 13 अप्रैल. पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि स्पेशल

इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें फिलहाल वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जांयमाल्या बागची की

बेंच ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले इस स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है। यदि ऐसे मतदाताओं को वोट देने की अनुमति दी जाती है, तो इससे उन मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होंगे जिनके नाम अंतिम सूची में शामिल हैं. बेंच ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद और मतदान से कुछ दिनों पहले अदालत का हस्तक्षेप चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है।

एमएसपी तय करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस

नई दिल्ली, 13 अप्रैल. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें सरकार को उचित तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने के लिए

निर्देश देने की मांग की गई है. महाराष्ट्र के किसान प्रकाश गोपालराव पोहरे, पुरुषोत्तम गावडे और विशाल ओमप्रकाश रावत द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में मांग की गई है कि फसलों पर

एमएसपी उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए. इसे तय करते समय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित खेती की वास्तविक लागत (सी2) को प्रभावी महत्व देना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जांयमाल्या बागची की पीठ ने इन दलीलों पर सुनवाई की. इस दौरान अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि यह मुद्दा देश भर के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक | पांच विभागों की 19,810 करोड़ रुपए की योजना पांच वर्ष तक चलती रहेंगी

सागर जिले की मिडवासा सिंचाई परियोजना को मंजूरी

2031 तक कृषि विभाग के प्रस्ताव रहेंगे बरकरार
27 गांवों की सिंचाई के लिए किसानों को मिलेगा लाभ
प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 13 अप्रैल. प्रदेश में पांच और विभागों की 19,810 करोड़ की योजनाओं और विकास कार्य अगले पांच वर्ष तक लगातार जारी रहेंगे. कैबिनेट ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परियोजना, महिला बाल विकास के कार्यों, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों तथा कृषि विभाग के प्रस्तावों को वर्ष 2031 तक बरकरार रखने की मंजूरी दे दी है.

कैबिनेट ने सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 286 करोड़ 26 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी है. इस परियोजना से सागर जिले की सागर तहसील के 27 गांवों की 7200 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए किसानों को लाभ मिलेगा. वहीं प्रदेश में 8 नए वन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति भी दी गई है. मैहर, मउर्जा, पांडुर्गा, धार में मनावर और पीथमपुर, इंदौर में लसुडिया और सांवेर एवं झाबुआ में पेटलावद में नये वन स्टॉप सेंटर का संचालन किया जाएगा. इसी तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति और मध्याह्न भोजन सहित कई योजनाओं/कार्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक

निर्णय के तहत लोक निर्माण के तहत अलग-अलग विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. इसके तहत बीओटी मार्गों का विकास एवं पर्यवेक्षण के लिए 150 करोड़, बीओटी परियोजनाओं की समाप्ति पर भुगतान के लिए 765 करोड़, एयूटी भुगतान के लिए 4,564 करोड़ और म.प्र. सड़क विकास निगम के लिए 5,322 करोड़ की स्वीकृति सहित 16वें वित्त आयोग की अवधि एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखे जाने की स्वीकृति दी गई है.

पांच वर्ष तक चलती रहेगी. इसके लिए 2,250 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. वहीं प्रदेश में भारत सरकार की सहायता से नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की योजना को आगामी 5 वर्षों तक चलाए जाने के लिए 1,674 करोड़ की स्वीकृति दी गई. इसमें जिला चिकित्सालय को चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध किया जाएगा. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वासन विभाग के तहत

स्वास्थ्य सेवाओं को 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखने के लिए लगभग 1,005 करोड़ खर्च होंगे. महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना एवं महिला हेल्पलाइन-181 योजना के संचालन के लिए 240 करोड़ 42 लाख और आगामी 5 वर्ष, 2026-27 से 2030-31 की अवधि तक संचालन एवं निरंतरता की स्वीकृति दी गई है.

विनय श्रद्धांगलि

स्व. प्रकाशचंद्रजी माहेश्वरी
जन्म : 15-11-1940 महाप्रयाण : 14-4-2005

धर्मयुक्तं सदाद्रं चित्तं पुरुषो कर्म हिते रतः ।
इच्छा बुद्धि प्रयासेन भवति प्राण प्रकाशकम् ।।

जो पुरुष अपने चित्त को सदा भावनामय तथा धर्म युक्त रखते हुए हितकारक कर्मों में लगा रहता है, वह इच्छा, बुद्धि और प्रयास से प्राणों को प्रकाशित करने वाला हो जाता है.

नव भारत Chronicle परिवार